

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में हरडा - मिमिपावेंग  
मोटर मार्ग का नव निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम रवथोली

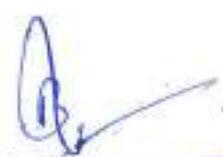
तहसील \_\_\_\_\_ जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत हरडा - मिमिपावेंग में परियोजना के निर्माण हेतु \_\_\_\_\_ हे० आरक्षित वन भूमि \_\_\_\_\_ हे० सिविल सोयम भूमि 3.486 हे० वन पंचायत भूमि 1.190 हे० अर्थात् कुल 4.676 हे० वन भूमि का नो नो विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्याखिन्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रवथोली द्वारा दिनांक 21-2-2015 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्विकृत किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रवथोली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि नो नो प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

  
ग्राम पंचायत

ग्राम प्रधान / सरपंच  
मुहर सहित

  
न्यायक अल्मोड़ा  
जिला अल्मोड़ा

प्रारूप -23.1

दिनांक 21.2.015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत रुचोली

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
		गोविन्दकि
		गदिपालकि
		गोविन्दराम
		गोपालकि
		देवप्रती देवी
		कान्हा देवी
		इंदरी देवी
		गोहनी देवी

ग्राम प्रधान / सरपंच

परियोजना का नाम -

जनपद अल्मोड़ा में डूरडा - विभिन्नालेण मोटर  
मार्ग

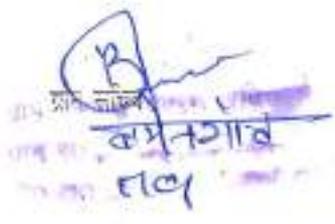
इन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बमनगाँव  
तहसील \_\_\_\_\_ जिला अल्मोड़ा  
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत डूरडा - विभिन्नालेण मो परियोजना के निर्माण हेतु ( \_\_\_\_\_  
हे० आवेदित वन भूमि \_\_\_\_\_ हे० सिविल सोयम भूमि 3.486 हे० वन पंचायत भूमि 1.190 हे०) अर्थात् कुल 4.676  
हे० वन भूमि का बोरो मि० विनाय / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन  
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बमनगाँव द्वारा दिनांक 21.2.15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक  
में प्रयोज्य एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार  
अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।  
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्विकृत किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं  
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का इनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बमनगाँव के  
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि बोरो मि० प्रयोज्य एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

  
ग्राम पंचायत बमनगाँव  
एलए

प्रधान  
ग्राम पंचायत बमनगाँव  
वि० ग्राम प्रधान / सरपंच  
मुहर सहित  
गुलशुक्ल

  
अल्मोड़ा

दिनांक 21.2.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत ...वामनगोबि.....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	आनन्द गिरी	आनन्द गिरी
	चन्द्रका	चन्द्रका
	नवीन चन्द	नवीन चन्द
	सुरेश चन्द	सुरेश चन्द
	मोहन गिरी	मोहन गिरी
	कृष्णा नन्द	कृष्णा नन्द

ग्राम प्रधान / सचिव

नवीन चन्द

मोहन गिरी  
आनन्द गिरी

परियोजना का नाम :-

अमरपद अल्मोड़ा में हरम (मिडिफिकेशन)  
प्रोड्यूसर्स को-ऑपरेटिव सोसायटी

वन अधिकार अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम घारखेवू

तहसील \_\_\_\_\_ जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत हरम (मिडिफिकेशन) प्रोड्यूसर्स को-ऑपरेटिव सोसायटी परियोजना के निर्माण हेतु (

\_\_\_\_\_ हे० आरक्षित वन भूमि \_\_\_\_\_ हे० सिविल सोयम भूमि 3.486 हे० वन पंचायत भूमि 1.196 हे०) अर्थात् कुल 4.676

हे० वन भूमि का लो० वि० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्याखति करने हेतु अर्पण प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत घारखेवू द्वारा दिनांक 21.2.05 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपरोक्त सभी बातों पर ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम घारखेवू के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो० वि० वि० प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

B  
ग्राम प्रधान  
पता: \_\_\_\_\_  
जिला: \_\_\_\_\_  
तहसील: \_\_\_\_\_



ग्राम प्रधान / सरपंच  
मुहर सहित  
सरपंच वन पंचायत  
घारखेवू  
सम्भागावधि (अल्मोड़ा)

दिनांक 21.2.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत दरभंगा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	प्रभर नाथ	प्रभर नाथ
	जोगुला देवी	जोगुला देवी
	पार्वती देवी	
	दीपा देवी	
	लीला देवी	
	शान्ती देवी	

ग्राम प्रधान / सरपंच

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में हरण-मिडिया हॉल मोरहा गार्ड

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम जाख / परछा

तहसील सल्ट जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत हरण मिडिया हॉल मोरहा गार्ड परियोजना के निर्माण हेतु (.....  
 हे० अरक्षित वन भूमि ..... हे० सिविल सोयम भूमि 3.486 हे० वन पंचायत भूमि 1.190 हे०) अर्थात् कुल 4.676

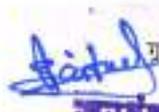
हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जाख द्वारा दिनांक 21-2-15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जाख के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लो.नि.वि. प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

  
 ज. प्रसाद  
 ग्राम पंचायत जाख

मांझई देवी  
 प्रधान  
 ग्राम पंचायत जाख  
 सल्ट (अल्मोड़ा)

  
 सरवेश  
 ग्राम प्रधान / सरपंच  
 मुहर सहित  
 वन पंचायत जाख  
 पट्टी नं-7 गल्ट  
 पो- जाख (जिला-अल्मोड़ा)

उमादेवी  
 सहायक  
 क्षेत्र पंचायत जाख  
 पी.ओ. जाख वि. सल्ट  
 जिला अल्मोड़ा

दिनांक 21.2.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत जाख / परभूड़ा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	च-दत्तसिंह	नाम गोविन्दसिंह
	श्री (दीप)	हरी सिंह
	श्रीरामसिंह	गीता देवी
	श्री	श्री (दीप)
	माधोसिंह	श्रीपालसिंह
	श्री	टीकाराम

मांगई देवी  
प्रधान  
ग्राम पंचायत जाख  
सल्ट (अल्मोड़ा)

  
सरपंच  
जन पंचायत जाख  
पट्टी तालाब मल्ट  
पो. जाख (जिला-अल्मोड़ा)

ग्राम प्रधान / सरपंच

श्रीदेवी  
सदस्य  
क्षेत्र पंचायत जाख  
पो. जाख वि. क. सल्ट  
जिला अल्मोड़ा

परियोजना का नाम -

जनपद अल्मोड़ा में हरण-भिक्रिया हेतु मोटर रोड

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम जाख  
 तहसील \_\_\_\_\_ जिला अल्मोड़ा  
 अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत हरण भिक्रिया हेतु मोटर रोड परियोजना के निर्माण हेतु ( \_\_\_\_\_ हे० आरक्षित वन भूमि \_\_\_\_\_ हे० सिविल सोयम भूमि 3.486 हे० वन पंचायत भूमि 1.190 हे०) अर्थात् कुल 4.676 हे० वन भूमि का ला० नि० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जाख द्वारा दिनांक 21.2.15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयाक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जाख के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि ला० नि० वि० प्रयाक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

  
 ग्राम सचिव

मांगई देवी  
 प्रधान  
 ग्राम पंचायत जाख  
 सख्त (अल्मोड़ा)

अमल  
 सरपंच  
 ग्राम प्रधान / सरपंच  
 मुहर सहित  
 वन पंचायत जाख  
 पट्टी नं० १४४  
 पी० जाख (जिला-अल्मोड़ा)

अमल देवी  
 सदस्य  
 क्षेत्र पंचायत जाख  
 पी० जाख वि० नं० १४४  
 जिला अल्मोड़ा

दिनांक 21.2.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत .....जान.....

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	<u>चन्द्रशक्ति</u>	नाम गोविन्द रिच
	<u>श्री (श्रीधर)</u>	श्रीशक्ति गीता देवी
	<u>सुशाला देवी</u>	दुम्कमराज
	<u>माधो देव</u>	मोहनराज
	<u>श्री</u>	उदेराम
	<u>श्री</u>	

ग्राम प्रधान / सरपंच

मांगई देवी  
प्रधान  
ग्राम पंचायत जान  
साल्ट (अल्मोड़ा)

श्री  
सरपंच  
ग्राम पंचायत जान  
पट्टी स-प: साल्ट  
को. जान (जिला-अल्मोड़ा)

श्री देवी  
सरपंच  
क्षेत्र पंचायत जान  
पट्टी स-प: साल्ट  
जिला अल्मोड़ा

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में डरडा - 1 विधियालय  
मोटर गाडी का चक्र निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण - पत्र

ग्राम पंचायत का नाम

डुगरी / दरमौली

तहसील

जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत डरडा - 1 विधियालय में परियोजना के निर्माण हेतु  
हेतु आरक्षित वन भूमि 3.486 हेतु सिविल सोयम भूमि 1.198 हेतु पंचायत भूमि 4.864.678  
हेतु वन भूमि का कोई भी विभाग / संस्था के फार्म में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत डुगरी / दरमौली द्वारा दिनांक 21/2/15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोज्य एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम डुगरी / दरमौली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि कोई भी - प्रयोज्य एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

  
ग्राम पंचायत  
अल्मोड़ा

ग्राम प्रधान / सरपंच  
मुहर सहित  
  
विकास

प्रारूप -23.1

दिनांक 21/2/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
 ग्राम पंचायत बुमरा / हरमोवा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
		उत्तम सिंह प्रतापराय
		दीन सिंह धना देवी
		रुद्रमणी

ग्राम प्रधान / सरपंच

~~ग्राम प्रधान~~  
 ग्राम सभा  
 विकास कार्य सचिव (बुमरा)

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा में डूरडा - मिथियालैंग  
मोटर मार्ग का नया निर्माण

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम तराडी  
तहसील \_\_\_\_\_ जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र  
उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत डूरडा मिथियालैंग प्रोजेक्ट परियोजना के निर्माण हेतु (\_\_\_\_\_  
हे० आवंटित वन भूमि \_\_\_\_\_ हे० सिविल सोयन भूमि 3.686 हे० एवं प्रयोज्य भूमि 1190 हे०) अर्थात् कुल 4.676  
हे० वन भूमि का मो० मि० विमान / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन  
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तराडी द्वारा दिनांक 21-02-2015 को सम्बन्ध ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक  
में प्रयोज्य एजेन्सी द्वारा आवंटित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार  
अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवंटित वन भूमि में आदिवासी अथवा किलो गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।  
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं  
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवंटित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हानन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तराडी के  
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि मो० मि० प्रयोज्य एजेन्सी का परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

श्री. [Signature]  
ग्राम सभा / सरपंच  
ग्राम तराडी  
जिला अल्मोड़ा

ग्राम प्रधान / सरपंच  
गृहर सल्लि

[Signature]  
श्री. [Signature]  
ग्राम प्रधान  
ग्राम पंचायत तराडी  
जिला अल्मोड़ा

दिनांक 21-02-2015 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
 ग्राम पंचायत बखडी

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	पूरन सिंह	पूरन सिंह
	भुवन सिंह	भुवन सिंह
	हरिन्द्र सिंह	Harinder
	गंगा देवी	गंगा देवी

ग्राम प्रधान / सरपंच

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

**ग्रामपाल**  
 ग्राम पंचायत बखडी  
 पंचायत क्षेत्र (बखडी)

परियोजना का नाम :-

हरडा भिक्खासैन मोटर मार्ग

इन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम बमोडा  
तहसील \_\_\_\_\_ जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत हरडा भिक्खासैन मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु ( \_\_\_\_\_ हे० आवंटित वन भूमि \_\_\_\_\_ हे० सिविल सोवम भूमि 3.486 हे० वन पंचायत भूमि 1.190 हे०) अर्थात कुल 4.676 हे० वन भूमि का को० सी० विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यापनित करने हेतु आवंटन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के दिवस में ग्राम पंचायत बमोडा द्वारा दिनांक 21/2/15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक में प्रवोक्ता एजेन्सी द्वारा आवंटित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवंटित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके आतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवंटित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बमोडा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि को० सी० प्रवोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिवसे जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

शान्ती देवी

उपान ग्राम पंचायत बमोडा  
को० सी० तहसील (अल्मोड़ा)

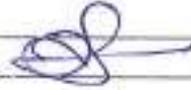
ग्राम प्रधान / सरपंच  
मुहर सहित

ग्राम मुखिया \_\_\_\_\_  
कोष अधिकारी \_\_\_\_\_  
को० सी० \_\_\_\_\_

सुरांज

सरपंच  
वन पंचायत बमोडा  
को०-तया (अल्मोड़ा)

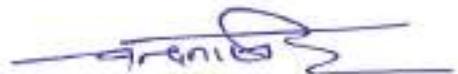
दिनांक 21/2/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत बमोड़ा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
	दलीप सिंह	
	आनन्दसिंह लड़ियल	
	गोपालराम	
	बि लाल रे	

ग्राम प्रधान / सरपंच

शान्ता देवी  
शान्ता देवी

ग्राम प्रधान पंचायत बमोड़ा  
'क' स्का' गांव (अल्मोड़ा)



सरपंच

ग्राम पंचायत बमोड़ा  
पोस्ट-सया (अल्मोड़ा)

परियोजना का नाम -

जनपद अल्मोड़ा में हरडा - अभिनिर्माण  
मोटर मार्ग ।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

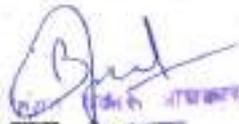
ग्राम पंचायत का नाम तथा  
तहसील \_\_\_\_\_ जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत हरडा - अभिनिर्माण मो.म. परियोजना के निर्माण हेतु ( \_\_\_\_\_  
हे० आवंटित वन भूमि \_\_\_\_\_ हे० सिविल सोपम भूमि 3.486 हे० वन पंचायत भूमि 1.190 हे०) अर्थात् कुल 4.676  
हे० वन भूमि का मो.मो.वी. विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन  
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तथा द्वारा दिनांक 21-2-15 को सम्पन्न ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक  
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवंटित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार  
अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवंटित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।  
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्विकृत किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं  
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवंटित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तथा के  
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि मो.मो.वी. प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

  
ग्राम सचिव  
तथा  
जिला अल्मोड़ा

  
ग्राम सभा - तथा

ग्राम प्रधान / सरपंच  
मुहर सहित  
हेमा देवी  
ग्राम पंचायत नया  
जिला अल्मोड़ा

प्रारूप -23.1

दिनांक 21-2-15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत तथा

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
		देव सिंह
		मोहम्मद शेरी
		शुभर रावत
		एवुशाल सिंह
		देव सिंह
		किशन सिंह

  
सरपंच  
ग्राम सभा-तथा

ग्राम प्रधान / सरपंच

  
हस्ताक्षर  
ग्राम पंचायत तथा  
दि. 21-2-15 (वर्षा 2015)

परियोजना का नाम :-

जनपद अल्मोड़ा के इलाहाबाद-मिन्निवासीय मोटर रोड

इन अधिकार अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण -पत्र

ग्राम पंचायत का नाम पीपलगांव  
तहसील मिन्निवासीय जिला अल्मोड़ा  
अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत इलाहाबाद (मिन्निवासीय मो.प्र.) परियोजना के निर्माण हेतु  
हेतु आरक्षित वन भूमि हेतु सिविल सोपम भूमि 3.486 हेतु वन पंचायत भूमि 1.190 हेतु अर्थात् कुल 4.676  
हेतु वन भूमि का अनापत्ति विभाग / संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन  
प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत पीपलगांव द्वारा दिनांक 21.2.15 को सम्बन्धित ग्राम सभा / ग्राम पंचायत की बैठक  
में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार  
अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य है अथवा नहीं।  
उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्वष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा / कृषि कार्य नहीं  
किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।  
चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम पीपलगांव के  
ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अनापत्ति प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

ग्राम सचिव

~~ग्राम पंचायत अनापत्ति प्रमाण पत्र  
ग्राम पंचायत  
मिन्निवासीय जिला अल्मोड़ा~~

गंगादेवी  
प्रधान  
ग्राम पंचायत - पीपलगांव  
पो-कोटागियाई  
मिन्निवासीय जिला अल्मोड़ा

ग्राम प्रधान / सरपंच  
मुहर सहित

Handing  
प्रधान  
वन इलाहाबाद पीपलगांव  
मिन्निवासीय जिला अल्मोड़ा

दिनांक 21.2.15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
ग्राम पंचायत पीपलगाँव

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित बरिष्ठ की ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	मोहनसिंह	मोहनसिंह
2-	रामचंद्रसिंह	रामचंद्रसिंह
3-	जीवन सिंह	जीवनसिंह
4-	वामन सिंह	वामनसिंह
5-	फकीर सिंह	फकीरसिंह
6	शान्ती देवी	शान्ती देवी

संग्राहकी

ग्राम पंचायत - पीपलगाँव  
पो - कोटागिवाड़ी  
प्रमाणिकित्वात्म (अ-बीका)

ग्राम प्रधान / सरपंच

हस्ताक्षर  
ग्राम पंचायत पीपलगाँव  
प्रमाणिकित्वात्म (अ-बीका)

प्रपत्र-23

परियोजना का नाम :- हरणा - धिकियासेन - मोरर मार्ग

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम तडा  
तहसील सह, जिला अजमेर

उत्तराखण्ड में जनपद अजमेर के अन्तर्गत हरणा - धिकियासेन परियोजना के निर्माण हेतु (140 हे० आरक्षित वन भूमि, 2 400 हे० सिविल सोयम भूमि, 1 140 हे० वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 4 600 वन भूमि का अजमेर विभाग/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। 21-2-08

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत तडा द्वारा दिनांक.....को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। \* उपरिष्ठत सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम तडा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि अजमेर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

अजमेर  
ग्राम पंचायत  
वि० तडा  
ग्राम सचिव

अजमेर  
क्षेत्र पंचायत डाय  
वि० अजमेर

ह०/-  
ग्राम प्रधान  
अजमेर  
ग्राम पंचायत  
वि० तडा

नोट :- \* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।  
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

परियोजना का नाम :- हरणा - धिकियासैण मोरर बाग प्रपत्र-23.2

कार्यालय उप जिलाधिकारी, सतलु  
 अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत  
 प्रमाण-पत्र  
 उपखण्ड स्तरीय समिति, सतलु

उपखण्ड सतलु परिक्षेत्र के अन्तर्गत हरणा - धिकियासैण  
 हे० आरक्षित वन भूमि, — हे० सिविल एवं शीघ्र वन भूमि ..... हे०  
 वन पंचायत भूमि, अर्थात् कुल 4.676 हे० वन भूमि ) का  
कोक निर्यात विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित  
 जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के  
 अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील सतलु) की दिनांक 21-2-05 को  
 सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)  
 अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक  
 श्री सतलु सतलु, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की  
 अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

- |    |                         |                           |             |            |
|----|-------------------------|---------------------------|-------------|------------|
| 1- | श्री <u>सतलु सतलु</u>   | उपजिलाधिकारी              | <u>सतलु</u> | अध्यक्ष    |
| 2- | श्री <u>कोक निर्यात</u> | उप प्रमाणीय वनाधिकारी     | <u>सतलु</u> | सदस्य      |
| 3- | श्री <u>सतलु सतलु</u>   | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | <u>सतलु</u> | सदस्य/सचिव |
| 4- | श्री <u>सतलु सतलु</u>   | बी०डी०सी० क्षेत्र         | <u>सतलु</u> | सदस्य      |

*Handwritten signature and initials*

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी  
 की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया  
 कि हरणा - धिकियासैण मोरर बाग

परियोजना हेतु 4.676 वन  
 भूमि कोक निर्यात विभाग

प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों  
 के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त  
 भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग  
 हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रमाणीय वनाधिकारी, सतलु द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य  
 परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008  
 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन  
 अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया  
 है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में  
 उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड २४०८ परिक्षेत्र के अन्तर्गत  
५२७१-१६ कृषि क्षेत्र परियोजना के निर्माण हेतु  
हेठ वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सखाम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर  
प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- २४०८  
जनपद ४७७१३१

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, शुल्का को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति  
तहसील- २४०८  
जनपद ४७७१३१

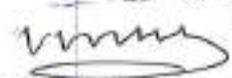


A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Vinod Kumar Suman, I.A.S. Deputy Commissioner, Almora on date 25/02/15 at time 3:00 PM at Almora, in which application claiming rights of ..... area measuring ..... hect. for the Construction of Harara Bhikiyasain M.I.R. of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of Almora sub division were discussed to consider the same of admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above for diversion of land for the said purpose.

Place : Almora

Date :

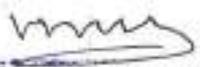
  
25/02/15  
विनोद कुमार सुमन  
Deputy Commissioner  
Almora

(Full name of the official seal of the District Collector)

It is further certified that

S.N.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of right under the FRA has been carried out for the entire <del>2362</del> <sup>4.676</sup> het. of forest area proposed for diversion/copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights committee(s) and the District level Committee are enclosed annexure 1 to annexure.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for Facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been Complete and the Gram Sabhas have given their consent to it.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other Traditional forest Dwellers there is no objection certificate of concerned motor road is affixed in the forest file
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and preagricultural communities.	Not applicable as there are no habitats belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers.

Encl:As above

  
25.02.15  
विभागाधिकारी  
Signature  
अमरावती.

(Full name of the official seal of the District Collector)

**FORM-1**  
**Government of Uttarakhand**  
**Office of the District Collector : Rudraprayag**

No :.....

Dated:.....

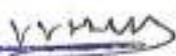
**TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN**

In Compliance of the Ministry of Environment and Forest(MoEF), Government of India's letter No:- 11-9/98-EC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers) Recognition of Forest Right, Act 2006(FRA, for Short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 23013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of liner projects. It is certified that.....hectares of forest land proposed to be diverted in favor of Rural Development Dept. Uttarakhand (Name of user agency) for Construction of.....Hanra - Bhikyasian motor Road.....  
.....  
(Purpose for diversion of forest land) in Almora.....district falls within jurisdiction of Jaya.....village(s) in salt.....Tehsils.

It is further Certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 5.676.....Hactares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the forest Rights Committee(s), Gram sabha(s), Sub-Division Level committee(s) and District Level Committee are enclosed as annexure I to-annexure.
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) to the FRA have completed and the Gram sabhas given their consent of it.
- (c) The proposal dose not involve recognized of primitive Tribble Groups and pre-agricultural communities.

Encl:As above

  
25/02/15  
Signature  
District Collector

(Full name of the official seal of the District Collector)

प्रपत्र-23.4

परियोजना का नाम :- हरद्वारा सिव्हालेन मोटर मार्ग

जिलाधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत प्रस्तावित हरद्वारा सिव्हालेन मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 4.676 हे० वन भूमि ला.नि.वि. (प्रयोक्ता एजेन्सी) को प्रस्तावित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11-9/98-एफ०सी० दिनांक 05-02-2013 के द्वारा रेखाकार (linear) प्रयोजनों यथा-सड़क, नहर, पारिषद लाईन, ओ०एफ०सी० कोबिल व पाईपलाईन बिछाने आदि के प्रकरणों को वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों से मुक्त किया गया है। विषयगत परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन व कृषि भूमि पर आदिवासी जनजाति समूह (Primitive Tribal Groups) व आदिवासी कृषि समुदाय (Pre Agricultural Tribal Groups) प्रभावित नहीं हो रहे हैं।

  
जिला समान कल्याण अधिकारी  
अल्मोड़ा

  
25.02.15  
जिला अधिकारी  
अल्मोड़ा  
जिलाधिकारी